

भारत सरकार  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2181  
जिसका उत्तर बुधवार, 12 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

### भोजन की बर्बादी

2181. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2022-23 जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान 2019 की तुलना में 2022-23 में 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 राज्यों के एसएफएसआई अंकों में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय घरों में प्रतिवर्ष 68.7 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो जाता है और घरों में भोजन की बर्बादी के मामले में यह विश्व में दूसरे स्थान पर है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

### उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): जी हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) जारी करता है, जो खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंक और अंक अनुलग्नक में संलग्न हैं।

(ख): विभिन्न एसएफएसआई में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित अंकों की तुलना खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई समस्याओं और प्रगति का विश्लेषण करने और उसे दर्शाने के लिए नहीं की जा सकती है, क्योंकि मापदंड स्थिर नहीं होते हैं और समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं।

(ग): जैसा कि, यूएनईपी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 का अनुमान है कि 2022 में भारत में खाद्य अपव्यय 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से काफी कम है।

(घ): केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूली पाठ्यक्रम में भोजन की बर्बादी की रोकथाम पर एक अध्याय शामिल करें, ताकि युवा विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें

भोजन की बर्बादी की रोकथाम के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। एफएसएसएआई ने खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए सक्रिय रूप से निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- i. “सेव फूड शेयर फूड” पहल का उद्देश्य खाद्य कैटरर्स सहित खाद्य उद्योग में खाद्य अपव्यय को रोकने के लिए सरप्लस खाद्य दान को बढ़ावा देना है।
- ii. सरप्लस खाद्य वितरण एजेंसियों की न्यूनतम पहुंच की समस्या से निपटने के लिए, भारतीय खाद्य साझाकरण गठबंधन (आईएफएसए) के रूप में सरप्लस खाद्य वितरण एजेंसियों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क बनाया गया है। आईएफएसए के अंतर्गत 82 एजेंसियां पंजीकृत हैं, जो 90 से अधिक शहरों तक पहुंच रही हैं। शेयर फूड के लिए एक समर्पित वेबसाइट है, जो आईएफएसए सदस्यों की शहरवार सूची, खाद्य अपव्यय की रोकथाम आदि की जानकारी प्रदान करती है।
- iii. एफएसएसएआई नागरिकों और खाद्य व्यवसायों को खाद्य अपव्यय की रोकथाम और सरप्लस भोजन दान करने के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

\*\*\*\*\*

"भोजन की बर्बादी" के संबंध में दिनांक 12.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2181 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तालिका 1: बड़े राज्यों के लिए सूचकांक रैंकिंग

तालिका 1: बड़े राज्यों के लिए सूचकांक रैंकिंग								
क्र. सं.	बड़े राज्य	मानव संसाधन और संस्थागत डेटा	अनुपालन	खाद्य परीक्षण-अवसंरचना और निगरानी	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	उपभोक्ता सशक्तिकरण	एसएफएस आई रैंक में सुधार	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4.5	10	1	4.5	4	0	24
2	असम	2.5	5	6	2.5	6	0	22
3	बिहार	3	8	5	3.5	1	0	20.5
4	छत्तीसगढ़	3.5	10	6	5.5	2	0	27
5	गुजरात	10	12	13.5	4	9	0	48.5
6	हरियाणा	5.5	12	7.5	3	5	0	33
7	हिमाचल प्रदेश	6.5	18	7	6.5	3	0	41
8	झारखंड	5	4	5	4	2	0	20
9	कर्नाटक	7.5	11	5.5	6	7	0	37
10	केरल	8.5	15	13.5	8	16	2	63
11	मध्य प्रदेश	8.5	11	8	7.5	16	5	56
12	महाराष्ट्र	10	11	4	5	15	0	45
13	ओडिशा	5.5	10	6.5	4	3	0	29
14	पंजाब	10.5	18	7	7	13	2	57.5
15	राजस्थान	11.5	12	8.5	3	8	2	45
16	तमिलनाडु	10.5	12	9	8	17	0	56.5
17	तेलंगाना	7	7	7.5	4.5	4	2	32
18	उत्तर प्रदेश	9.5	16	6	4	15	2	52.5
19	उत्तराखंड	7.5	13	7	5.5	6	0	39
20	पश्चिम बंगाल	12	11	9	5	11	0	48

तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए सूचकांक रैंकिंग

तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए सूचकांक रैंकिंग								
क्र. सं.	छोटे राज्य	मानव संसाधन और संस्थागत डेटा	अनुपालन	खाद्य परीक्षण-अवसंरचना और निगरानी	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	उपभोक्ता सशक्तिकरण	एसएफएस आई रैंक में सुधार	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	4	14	1.5	3	1	2	25.5
2	गोवा	7.5	9	8.5	5	13	8	51
3	मणिपुर	4	14	6.5	1.5	11	3	40
4	मेघालय	6.5	4	8	4	6	2	30.5
5	मिजोरम	3	9	0.5	1	1	0	14.5
6	नागालैंड	4	5	7	3	8	2	29
7	सिक्किम	8	11	2.5	5	10	3	39.5
8	त्रिपुरा	4	7	7	2.5	4	0	24.5

तालिका 3: संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए सूचकांक रैंकिंग

तालिका 3: संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए सूचकांक रैंकिंग								
क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)	मानव संसाधन और संस्थागत डेटा	अनुपालन	खाद्य परीक्षण-अवसंरचना और निगरानी	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	उपभोक्ता सशक्तिकरण	एसएफएस आई रैंक में सुधार	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	14	1.5	5	4	0	30.5
2	चंडीगढ़	5.5	14	2	5.5	15	3	45
3	दादरा एनएच और डीडी	3	11	1.5	3	5	2	25.5
4	दिल्ली	6.5	14	6	6	14	3	49.5
5	जम्मू एवं कश्मीर	10.5	16	8	5	12	8	59.5
6	लद्दाख	11.5	14	0.5	4	9	2	41
7	लक्षद्वीप	1	3	0	0	0	0	4
8	पुदुचेरी	3	4	2.5	0.5	2	0	12

\*\*\*\*\*